Industrial Dispute Act

What do you mean by Industrial Dispute

भारतीय औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 (ID Act 1947) किसी भी औद्योगिक प्रतिष्ठान में औद्योगिक विवादों की जांच और निपटान के लिए अधिनियमित किया गया है।

औद्योगिक विवाद अधिनियम, "औद्योगिक विवाद" को श्रमिकों और नियोक्ताओं के बीच या कामगारों और कामगारों के बीच विवाद या अंतर के रूप में परिभाषित करता है, जो रोजगार या गैर रोजगार या रोजगार की शर्तों या श्रम की शर्तों से जुड़ा है। एक व्यक्तिगत कामगार की बरखास्तगी को एक औद्योगिक विवाद माना जाता है।

ID Act नियोक्ता और कामगारों से मिलकर वर्क्स कमेटी के गठन के लिए प्रदान करता है, जो नियोक्ता और कामगारों के बीच सौहार्द और अच्छे संबंधों को सुरक्षित रखने और बनाए रखने के उपायों को बढ़ावा देता है और कुल अंत तक किसी भी भौतिक मतभेद को हल करने का प्रयास करता है।

ID Act विवादों के निपटारे के लिए सुलह अधिकारियों, सुलह बोर्ड, श्रम न्यायालयों, श्रम न्यायालयों, न्यायाधिकरणों और राष्ट्रीय न्यायाधिकरणों की नियुक्ति का प्रावधान करता है। विवादों के निपटारे के लिए मान्यता प्राप्त एक अन्य तरीका मध्यस्थता है,

माध्यम से है। औद्योगिक विवाद अधिनियम
विवादों को निपटान का एक कानूनी तरीका
प्रदान करता है। अधिनियम के तहत प्रदान की गई
निवारक मशीनरी का लक्ष्य एक ऐसा वातावरण
बनाना है जहां विवाद पैदा ही न हो। ID Act,
अनुचित श्रम प्रथाओं को प्रतिबंधित करता है जो
पांचवीं अनुसूची, हड़तालों और तालाबंदी (कुछ
परिभाषित शर्तों के तहत और उचित नोटिस के अलावा)
में परिभाषित है। यह अवैध हड़तालों और तालाबंदी
और अनुचित श्रम प्रथाओं और छंटनी और
छंटनी के प्रावधानों के साथ-साथ उसके देय
मुआवजे के लिए दंड का भी प्रावधान करता है।
ID Act में प्रावधान है कि एक नियोक्ता जो एक
औद्योगिक प्रतिष्ठान को बंद करने का इरादा रखता है
उस तारीख से कम से कम 90 दिन पहले पूर्व अनुमति
प्राप्त करेगा, जिस दिन वह औद्योगिक प्रतिष्ठान
को बंद करने का इरादा रखता है, इसके कारण को
बताते हुए।

→ औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 वह
अधिनियम है जो श्रम कानूनों को नियंत्रित करता है
क्योंकि यह सभी कामगारों, या भारतीय मुख्य
भूमि पर कार्यरत सभी लोगों से संबंधित है।
यह 1 April 1947 को लागू हुआ।

पूंजीपतियों या नियोक्ता और
श्रमिकों के बीच हमेशा मतभेद होता था और
इस प्रकार, यह इन दोनों समूहों के बीच और
भीतर, बहुत सारे संघर्षों को जन्म देता है। इसलिए,
इन मुद्दों को सरकार के ध्यान में लाया गया

और इसलिए उन्होंने इस अधिनियम को पारित करने का निर्णय लिया। इस अधिनियम का गठन पार्टियों के बीच औद्योगिक विवादों में शांति और सद्भाव लाने और उनके मुद्दों को शांतिपूर्ण तरीके से हल करने के मुख्य उद्देश्य से लिया गया था।

विस्तार और कवरेज

यह औद्योगिक विवादों की जाँच और निपटान के लिए और विशिष्ट उद्देश्यों के लिए भी बनाया गया अधिनियम है। यह अधिनियम केन्द्र सरकार के अधिकार के तहत या किसी रेलवे, संगठन द्वारा या किसी ऐसे नियंत्रित उद्योग से संबंधित किसी भी उद्योग के आसपास केन्द्रित है जिसे केन्द्र सरकार द्वारा इस लाभ के लिए इंगित किया जा सकता है।

अधिनियम की मुख्य विशेषताएं

यह अधिनियम है कि बाद में कामगारों और व्यवसायों के बीच अच्छे कामकाजी संबंधों और समझ के लिए उपायों को आगे बढ़ाने के लिए व्यवसायों और सभी कामगारों दोनों के लिए कार्य समिति के संबंध में विशिष्ट दिशा-निर्देश प्रदान करता है, और इसे समाप्त करने के लिए यह अतिरिक्त रूप से प्रतिज्ञा करता है ऐसे मुद्दों के संबंध में राय के विचारों में किसी भी भौतिक अंतर को हल करे।